क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

# दैनिक क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480

E-mail: krantisamay@gmail.com

सूरत, वर्ष: 02 अंक: 48, मंगलवार, 12 मार्च, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.

रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात

Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1


## पहला कॉलम

### पुलवामा हमले के आरोपी मसूद अजहर को भाजपा सरकार ने किया था आजादः राहुल गांधी

**नेशनल डेस्क।** कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से झूठे वादे किए। वह ससंद में मुझसे आंख से आंख नहीं मिला सके। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। पुलवामा हमले के पीछे जिस जैश के आतंकी मसूद अजहर का हाथ था उसे पहले बीजेपी की सरकार ने जेल से छुड़वाया था आपको याद होगा कि एनडीए की अंतिम सरकार के दौरान, वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मसूद अजहर को छोड़ने के लिए कंधार गए थे। कांग्रेस ने दो प्रधानमंत्री खोए हैं लेकिन पार्टी कभी किसी के आगे नहीं झुकी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की समझ में बड़ा अंतर है। मोदी जी रात 8 बजे अचानक नोटबंदी लागू कर देते हैं जिससे गरीबों को भारी नुकसान पहुंचा। गब्बर सिंह टैक्स से छोटे व्यापारियों को बर्बाद कर दिया। ये कांग्रेस पार्टी का कमाल है कि जैसे ही बोला जाता है चौकीदार, लोग जवाब में कहते हैं कि चोर है। भाजपा और अरएसएस की विचारधारा नफरत की है। लोगों को फैसला लेना है कि वह गांधी का हिंदुस्तान चाहते हो या गोडसे का हिंदुस्तान चाहते हैं। बीजेपी और ऋस्स की विचारधारा नफरत और डर की विचारधारा है, मैंने पीएम मोदी को पहचान लिया है। हमारी सरकार आने पर लोगों के लिए मिनिमम इनकम गारंटी योजना लागू करेंगे। मोदी जी ने लोगों से रोजगार का वादा किया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया।

### कांग्रेस और भाजपा के लिये नाक का सवाल बनी अमेठी

**अमेठी।** कहावत है कि केन्द्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है लेकिन लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान होने के साथ ही कांग्रेस के किले के तौर पर विख्यात अमेठी इस बार देश की सबसे पुरानी पार्टी के साथ ही भाजपा के लिये भी नाक का सवाल बन चुकी है। केंद्र की सत्ता की राह आसान बनाने वाले इस राज्य की अमेठी सीट पर दशकों से कांग्रेस एकछत्र राज करती आयी है। पिछले लोकसभा चुनाव में हालांकि मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कड़ी टक्कर दी थी। पिछले चुनाव में भाजपा ने छोटे पर्दे पर बहू के किरदार से चर्चित हुयी स्मृति को श्री गांधी के खिलाफ मैदान में उतारा था। वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता रहे डॉ. कुमार विश्वास और बसपा से धर्मेंद्र भी मैदान में थे। कांग्रेस के किले में सेंध लगाने की असफल कोशिश करने वाली भाजपा ने पिछले पांच साल के कार्यकाल के दौरान इस क्षेत्र में अपना दखल बनाये रखा है। केन्द्र के नरेन्द्र मोदी मंत्रिमंडल की अहम सदस्य स्मृति ने कांग्रेस अध्यक्ष के संसदीय क्षेत्र का इस दौरान कई बार दौरा किया और जनसभाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की। उधर केन्द्र सरकार ने भी अमेठी के विकास से संबधित योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई कोताही नहीं बरती।

## केरल निर्वाचन आयोग ने प्रचार में सबरीमला मुद्दे के इस्तेमाल के खिलाफ किया आगाह

**तिरुवनंतपुरम।**

केरल में राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने सोमवार को राज्य में राजनीतिक दलों को आगाह किया कि सबरीमला मंदिर मामले को चुनाव प्रचार का मुद्दा ना बनाए।

केरल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीकाराम मीना ने बताया कि 'सबरीमला मुद्दे' पर धार्मिक प्रोपेगैंडा फैलाना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा, 'धार्मिक भावनाएं उकसाना, उच्चतम न्यायालय के फैसले का किसी तरह इस्तेमाल करना, धर्म के नाम पर वोट मांगना या धार्मिक भावनाएं भड़काना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।' सीईसी ने यह भी कहा कि आयोग ऐसा कोई उल्लंघन नहीं करने देगा जिससे किसी खास राजनीतिक दल को दूसरे दल के मुकाबले लाभ मिलेगा। मीना ने कहा, 'सबरी भगवान के नाम पर सबरीमला मुद्दे पर धार्मिक प्रोपेगैंडा करना या भावनाएं भड़काना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन होगा।' उन्होंने कहा कि जहां तक केरल का संबंध है तो यह विवादित मामला है और राजनीतिक दलों को एक सीमा तय करने की जरुरत है कि किस हद तक इसका इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा, 'मंगलवार को, मैं इस संबंध में राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रहा हूं और मैं उनसे वोट मांगने के लिए इस धार्मिक भावना या धार्मिक परंपराओं का अनावश्यक इस्तेमाल ना करने का अनुरोध करुंगा क्योंकि इससे लोगों के लिए धार्मिक तनाव पैदा हो सकता है।' मीना ने कहा कि अगर यह होता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केरल में 23 अप्रैल को चुनाव होंगे।

लोकसभा चुनाव 2019:

# लोकसभा चुनाव 2019: चुनावी रणभेरी बज चुका है नजर होगी इन 8 पर

**नई दिल्ली।**

चुनावी रणभेरी बज चुकी है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार की वापसी होगी? सत्तारूढ़ एनडीए के सामने 10 ऐसी चुनौतियां हैं, जो राह में रोड़े अटकाती दिख रही हैं। सत्ता में वापसी तभी संभव है, जब एनडीए इनकी काट ढूंढ़ ले...

**दिल्ली में केजरीवाल**

दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी के कान खड़े हैं। यह वजह है कि बीजेपी कई सीटों पर नए चेहरों को आजमाने पर विचार कर रही है।

**यूपी में बुआ-बबुआ**

उत्तर प्रदेश में दूसरे सभी राज्यों से ज्यादा लोकसभा की 80 सीटें हैं और इसीलिए कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर निकलता है। 2014 में यूपी ने बीजेपी की झोली भरकर मोदी सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। मोदी लहर में बीजेपी ने यूपी में 71 सीटें और सहयोगी अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। सपा के हिस्से में 5 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। जबकि बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया था। इस लोकसभा चुनाव के पहले बीएसपी-एसपी ने पुरानी अदावतों को भुलाकर गठबंधन किया है और बुआ-बबुआ की जोड़ी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। राज्य में अपनी जमीन खो चुकी कांग्रेस ने भी प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी की जिम्मेदारी सौंपकर चुनौती पेश करने की कोशिश की है, साथ ही 'बैक चैनल' से बीएसपी-एसपी गठबंधन से भी बातचीत जारी है। यानी कि इस बार विपक्षी एकता की व्यूह को भेद पाना एनडीए के लिए आसान नहीं होगा।

**महाराष्ट्र में पवार**

महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। राज्य में बीजेपी अगुवाई वाली सरकार है, लेकिन राजनीति के पुराने धुरंधर और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार एनडीए के लिए चुनौती खड़ी कर सकते हैं। एनसीपी ने इस बार भी कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि अलग राग अलापने के बावजूद शिवसेना ने आखिरकार गठबंधन में बने रहने का फैसला लिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी ने 23 और शिवसेना ने 18 सीटें जीती थी। एनसीपी के खाते में 4 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। स्वाभिमानी पक्ष को 1 सीट मिली थी।

**ओडीशा में नवीन**

प्रदेश में लोकसभा की 21 सीटें हैं और 19 साल से राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेडी इस आम चुनाव में भी एनडीए के सामने चुनौती है। हालांकि, बीजेपी की भरपूर कोशिश इस बार बीजेडी को पछाड़ने की है। बीजेडी ना तो एनडीए के साथ है, ना ही यूपीए के। 2009 में बीजेडी ने एनडीए से नाता तोड़ा था। 2009 में बीजेडी ने 14 सीटें और 2014 में देशभर में मोदी लहर के बावजूद 20 सीटें बटोरने में कामयाबी पाई थी। बीजेपी को उम्मीद है कि प्रदेश की सत्ता विरोधी लहर का लाभ मिलेगा।

**गहलोत और कमलनाथ**

राजस्थान में लोकसभा की 25 और मध्यप्रदेश में 29 सीटें हैं। इन दोनों राज्यों में बीजेपी की सत्ता थी और 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को जबरदस्त जीत मिली थी। 2014 में राजस्थान की सभी सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, वहीं मध्यप्रदेश में 26 सीटें मिली थी। मध्यप्रदेश की 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से में थी। पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में राजस्थान और मध्यप्रदेश की सत्ता बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस के हाथों चली गई। अब राजस्थान में अशोक गहलोत और मध्यप्रदेश में कमलनाथ की सरकार है और एनडीए के लिए 2014 का प्रदर्शन दोहरा पाना काफी मुश्किल होगा।

**आंध्रप्रदेश में चंद्रबाबू**

आंध्र में लोकसभा की 25 सीटें हैं और सत्ताधारी टीडीपी के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडु इस बार बीजेपी विरोधी मोर्चे में पूरी तरह सक्रिय हैं। 2014 का चुनाव बीजेपी और टीडीपी ने साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन पिछले साल राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग उठाकर टीडीपी ने एनडीए से नाता तोड़ लिया। इसके बाद से तलवारें खिचीं हुई हैं। वहीं, वाईएसआर कांग्रेस सुप्रीमो जगनमोहन रेड्डी ने अभी तक एनडीए और यूपीए से दूरी दिखाने की कोशिश की है। 2014 में संयुक्त आंध्रप्रदेश की 42 सीटों में से टीडीपी ने 16 सीटें और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। टीआरएस को 11, वाईएसआर कांग्रेस को 9 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी।

**तेलंगाना में राव**

नए राज्य तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। सत्ताधारी टीआरएस ने हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत हासिल करते हुए वापसी की। मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ऐसे नेताओं में शामिल हैं, जो कि केंद्र में मोदी सरकार की जगह तीसरे मोर्चे की सरकार के लिए सबसे पहले अपनी सक्रियता दिखाई। उन्होंने कई क्षेत्रीय दलों से मुलाकात भी की थी।

**तमिलनाडु में स्टालिन**

तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। सत्ताधारी एआईएडीएमके की सुप्रीमो रहीं जयललिता और मुख्य विपक्षी डीएमके के सुप्रीमो रहे करुणानिधि के निधन के बाद राज्य के राजनीतिक काफी हालात बदले हुए हैं। एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ समझौता कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बीजेपी 5 सीटों और बाकी सीटों पर एआईएडीएमके के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन ने 20 सीटों पर उम्मीद खड़े करने का ऐलान किया है, जबकि बाकी सीटें कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई, वीसीके, आईयूएमएल, केएनएमडीके और आईजेके के हिस्से में रहेंगी। 2014 के आम चुनाव में एआईएडीएमके ने 37 सीटें जीतकर विरोधियों का सफाया कर दिया था। बीजेपी को 1 सीट मिली थी।

## किसान सम्मान निधि के तहत 2.6 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक 5,215 करोड़ रुपये का अंतरण

**नयी दिल्ली।** प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 2.6 करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को 5,215 करोड़ रुपये का अंतरण किया गया। पिछले महीने 2019-20 के अंतरिम बजट में सरकार ने इन किसानों को एक निश्चित न्यूनतम आय मुहैया कराने के लिए इस योजना की घोषणा की थी। आम चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने 75,000 करोड़ रुपये की इस योजना की घोषणा की थी। इसके तहत देश में दो हेक्टेयर से कम जोत वाले करीब 12 करोड़ किसानों को तीन किस्तों में 6,000 रुपये की न्यूनतम वार्षिक आय मुहैया करायी जानी है। अंतरिम बजट में सरकार ने इसके लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके तहत मार्च के अंत तक किसानों को 2,000 रुपये की पहली किस्त पहुंचानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की आधिकारिक शुरुआत 24 फरवरी को गोरखपुर में की थी। रविवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि इस योजना की घोषणा के 37 दिन के भीतर 2.6 करोड़ से अधिक छोटे एवं सीमांत किसानों को अब तक 5,215 करोड़ रुपये उनके बैंक खाते में अंतरित किए गए हैं।

### लोकसभा चुनावः तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा ने बुलाई मेनिफेस्टो पर बैठक

**नेशनल डेस्क।** लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी जीत के दावे करने शुरू कर दिये हैं। वहीं इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने आज संकल्प पत्र के लिए मेनिफेस्टो कमेटी की बैठक बुलाई है। समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अगुवाई करेंगे। जानकारी के अनुसार भाजपा की यह बैठक दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें संकल्प पत्र को लेकर मंथन किया जाएगा। बता दें कि भाजपा किसानों को साधने के लिए उनके सुझाव अपने 'संकल्प पत्र' में शामिल करेगी। पार्टी 'किसान के मन की बात, मोदीजी के साथ' नामक सत्र के माध्यम से किसानों की राय जानने का प्रयास करेगी। भाजपा नेताओं के अनुसार 2014 के चुनाव में भी कई तरह के सामाजिक समीकरणों की चर्चा थी, लेकिन नतीजों में वे नहीं चले। इस बार भी विपक्ष जिस तरह से सामाजिक समीकरणों को लेकर गणित बना रहा है। पार्टी के अनुसार 2019 में 2014 के चुनाव से भी बड़ी सफलता मिलेगी।

### टीएमसी ने शुरू की लोक सभा चुनाव की तैयारियां

**कोलकाता ।** पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने लोकसभा चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद विभिन्न स्थानों से चुनाव अभियान शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए टीएमसी प्रमुख एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को कालीघाट में पार्टी की 12 सदस्यीय चुनाव कोर टीम के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करेंगी। इस बैठक के बाद भावी उम्मीदवारों की घोषणा की तिथि घोषित होगी तथा उम्मीदवारों की सूची बुधवार या शुक्रवार तक जारी किये जाने की संभावना है। टीएमसी के एक वरिष्ठ नेता ने इस आशय की जानकारी दी। इससे पहले ममता ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव अभियान की रणनीति तय करने के लिए तीन मार्च को 12 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन किया था। टीएमसी की 12 सदस्यीय समिति में सुब्रत बख्शी, पार्थ चटर्जी, फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास, शुवेन्दु अधिकारी, अभिषेक बनर्जी, शशि पांजा, चंद्रिमा भट्टाचार्य, मलय घटक, ज्योतिप्रिया मल्लिक, ।

## पुलवामा में हमले के मास्टरमाइंड मुदस्सिर खान को ढेर कर दिया गया

श्रीनगर। १४ फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मुदस्सिर अहम खान को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। सुरक्षाबलों के लिए इसे बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सोमवार को हुए एक एनकाउंटर में तीन आतंकी मार गिराए गए। मारे गए आर्तकियों में जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर मुदस्सिर अहमद खान उर्फ मोहम्मद भाई भी शामिल है। जैश के कमांडर मुदस्सिर खान के परिवार ने उसके शव की शिनाख्त त्राल एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों में से एक के रूप

में की है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। अभी फरेंसिक रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान जेआईएम कमांडर मुदासिर खान उर्फ मोहम्मद भाई के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि शवों के डीएनए परीक्षण किए जाएंगे। जिस घर में आतंकवादी छिपे हुए थे, सुरक्षाबलों के अभियान में वह घर पूरी तरह से नष्ट हो गया।

सेना ने कहा है कि तीन आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी तक सिर्फ दो शव बरामद किए हैं। सोमवार रात त्राल के पिंगलिश इलाके में एनकाउंटर के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी मार गिराए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि मुदस्सिर उन तीन आतंकियों में से एक है जो मुठभेड़ में ढेर किए गए हैं। एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकियों के शव बुरी तरह से जल गए हैं और उनकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। सुरक्षाबलों ने आतंकियों की मौजूदगी का खुफिया इनपुट मिलने के बाद पिंगलिश इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च पार्टी पर जब घात लगाकर बैठे आतंकियों ने फायरिंग की तो यह अभियान एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया। इसके बाद सुरक्षाबलों ने जवाबी फायरिंग करते हुए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों में कम चर्चित मुदस्सिर को पुलवामा टेरर अटैक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस हमले में सीआरपीएफ के ४० जवान शहीद हो गए थे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पुलवामा के ही निवासी २३ साल का मुदस्सिर एक इलेक्ट्रिशन था और उसके पास ग्रैजुएट की डिग्री थी। अधिकारियों के मुताबिक आतंकी हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी और विस्फोटक का इंतजाम उसी ने किया था। त्राल के मीर मोहल्ले के रहने वाले मुदस्सिर ने २०१७ में एक ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद जॉइन किया था। बाद में उसे नूर मोहम्मद तांत्रे उर्फ नूर त्राली ने जैश में सक्रिय रूप से जिम्मेदारी सौंपी। नूर पर कश्मीर घाटी में आतंकी संगठनों को दोबारा उठ खड़े होने में मदद पहुंचाने का आरोप है। जनवरी २०१८ में लेथपोरा में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले में भी उसका नाम आया। इस हमले में पांच सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे।

पुलवामा हमले की जांच कर रही एनआईए ने २७ फरवरी को मुदस्सिर के घर पर छापा मारा था।

रमजान के दौरान वोटिंग पर चुनाव आयोग बोला

## त्योहार का रखा ध्यान, शुक्रवार को नहीं मतदान

नई दिल्ली। रमजान में मतदान के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी शुक्रवार या त्योहार के दिन मतदान नहीं हैं। आयोग ने कहा कि रमजान के पूरे महीने ही चुनाव न हों, ऐसा नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग का यह बयान उस मौके पर आया है, जब कई पार्टियां रमजान में मतदान होने के फैसले का विरोध कर रही हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि २ जून से पहले नई सरकार का गठन होना जरूरी था। ऐसे में इसे और टाला नहीं जा सकता था। साथ ही एक महीने तक चुनाव न हों, ऐसा भी संभव नहीं था। इसलिए आयोग ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि किसी भी शुक्रवार को अथवा किसी फेस्टिवल के दौरान मतदान न हो। चुनाव आयोग का कहना है कि हमारे पास इन तारीखों को बदलने का अथवा चुनाव के समय को आगे-पीछे करने का विकल्प ही नहीं था।बता दें कि तीन राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में वोटिंग की तारीखें रमजान के महीने में पड़ रही हैं। ऐसे में मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इन तारीखों में बदलाव की मांग की है। कोलकाता के मेयर और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता फिरहाद हाकिम ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है और हम उसका सम्मान करते हैं। हम चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन सात फेज में होने वाले चुनाव बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए कठिन होंगे।

## संपादकीय

# बढ़ी देश के मतदाताओं की जिम्मेदारी

निर्वाचन आयोग की ओर से आम चुनाव की तिथियां तय कर देने के साथ ही देश लोकतंत्र का उत्सव मनाने की दिशा में बढ़ चला है। पिछले आम चुनाव में मतदान के नौ चरणों के मुकाबले इस बार सात चरण घोषित होने से यह तो स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग पहले के मुकाबले कुछ और समर्थ हुआ है, लेकिन उसकी कोशिश यही होनी चाहिए कि चुनाव की प्रक्रिया कम से कम लंबी हो। आज के इस तकनीकी युग में अपेक्षाकृत छोटी चुनाव प्रक्रिया के लक्ष्य को हासिल करना कठिन नहीं होना चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया न केवल यथासंभव छोटी होनी चाहिए, बल्कि वह राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों के छल-कपट से मुक्त भी होनी चाहिए। यह सही है कि पहले की तुलना में आज की चुनाव प्रक्रिया कहीं अधिक साफ-सुथरी और भरोसेमंद है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि वह बेहद खर्चीली होने के साथ ही धनबल से भी दुष्प्रभावित होने लगी है। विडंबना यह है कि चुनाव लड़ने वाले इस आशय का शपथपत्र देकर छुट्टी पा लेते हैं कि उन्होंने तय सीमा के अंदर ही धन खर्च किया। यह विडंबना तब है जब हर राजनीतिक दल और खुद निर्वाचन आयोग भी इससे अवगत है कि आज चुनावों में किस तरह पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। अब तो हालत है कि पैसे बांटकर चुनाव जीत लेने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। समस्या यह है कि जहां जागरूक जनता चुनावी खामियों को दूर करने की जरूरत महसूस करती है वहीं राजनीतिक दल ऐसी किसी जरूरत पर ध्यान ही नहीं देते। यह अच्छा नहीं हुआ कि बीते पांच साल में न तो कोई ठोस राजनीतिक सुधार किया गया और न ही चुनावी सुधार। आम चुनाव को भले ही लोकतंत्र के उत्सव की संज्ञा दी जाती हो, लेकिन सच यह है कि इस उत्सव में राजनीतिक बैर भाव अपने चरम तक पहुंचता दिखता है। कई बार परस्पर विरोधी राजनीतिक दल-एक दूसरे के प्रति शत्रुवत व्यवहार करते हैं। वे न केवल अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति अशालीन-अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उन्हें बदनाम करने और नीचा दिखाने के लिए झूठ और कपट का सहारा भी लेते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं कि आम चुनाव के मौके पर राजनीतिक विमर्श रसातल में चला जाए। दुर्भाग्य से राजनीतिक दलों से यह उम्मीद कम ही है कि वे राजनीतिक शुचिता और लोकतांत्रिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में मतदाताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल सोच-समझकर करें। अपने देश में यह एक बीमारी सी है कि बाकी समय तो हम सब जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद को कोसते हैं, लेकिन वोट देते समय जाति-मजहब को ही महत्व दे देते हैं। जात-पांत के आधार पर राजनीति इसीलिए होती है, क्योंकि एक तबका इसी आधार पर वोट देता है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कई बार राष्ट्रहित के मसलों से अधिक महत्व संकीर्ण स्वार्थ को दे दिया जाता है। चूंकि आम चुनाव देश के भविष्य के साथ राजनीति की भी दशा-दिशा तय करते हैं इसलिए आम मतदाता का इस भाव से लैस होना जरूरी है कि वह वोट के जरिये एक महती काम करने जा रहा है।

# पुनरुद्धार से बदलेगी सूरत

काशी विश्वनाथ/ अवधेश कुमार

*मोदी विरोधियों का तर्क है कि वाराणसी की पहचान ही गलियों से है और अगर आप उसे ही नष्ट कर देंगे तो फिर यह वाराणसी नहीं होगा। वाराणसी में अनेक छोटे-छोटे प्राचीन मंदिर हैं, जिनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्त्व है जो पुनर्निर्माण योजना की भेंट चढ़ रहे हैं। माना जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब मंदिरों और मूर्तियों को ध्वस्त करना आरंभ किया तो काशीवासियों ने उनको अपने घरों के अंदर छिपा लिया था। चूंकि पुनर्निर्माण योजना में आसपास के मकानों को हटाना और गंगा तट तक सीधे रास्ता बनाना शामिल है इसलिए आरंभ में वहां केवल विध्वंस ही दिखता है।*

वाराणसी के धार्मिक-सांस्कृतिक महत्त्व को बताने की आवश्यकता नहीं। गंगा यहीं उत्तर वाहिनी होती है और द्वादश ज्योर्तिलिंगों में एक काशी पुराधिपति भी यहीं हैं। वाराणसी में पिछले करीब एक वर्ष से ज्यादा समय से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पुनर्निर्माण योजना को लेकर विरोध और समर्थन दोनों सघन हुए हैं। मोदी और भाजपा के सनातन विरोधियों के लिए तो यह सबसे बड़ा मुद्दा था ही, उनके समर्थकों का एक वर्ग भी विरोध में उतर गया। इनका मानना है कि मोदी वाराणसी की प्राचीनतम विशेषताओं को विकास की वेदी पर ध्वस्त कर रहे हैं। इसे राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की भी कोशिशें हुई हैं। मोदी वहां के सांसद हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी यह विषय उछला है। पिछले 8 मार्च को मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ धाम का शिलान्यास किया तो इसका विरोध स्वाभाविक था। इसे ''काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना' कहा गया है। विरोधी अपने स्टैंड पर कायम हैं और इसका उपहास उड़ा रहे हैं। दूसरी ओर मोदी ने संकल्प व्यक्त किया कि वे वाराणसी के कायाकल्प के साथ विश्वनाथ धाम का भी पुनरोद्धार करेंगे ताकि सोमनाथ की तरह यह भी भव्य हो, श्रद्धालुओं व साधकों को सारी सुविधायें सुलभ हों एवं यह तंग गलियों से मुक्त हो सके। वारणसी भारत के दक्षिण एवं उत्तर दोनों के लिए समान रूप से पवित्र स्थल है। बावजूद सच यही है कि वहां जाने वाले श्रद्धाभाव में भले कुछ न बोलें, पर बाधाएं व कठिनाइयों से उन्हें कदम-कदम पर चार होना पड़ता था। चारों तरफ से बने मकानों-दूकानों के बीच वहां पहुंचना भी सामान्य चुनौती नहीं है। मोदी विरोधियों का तर्क है कि वाराणसी की पहचान ही गलियों से हैं और अगर आप उसे ही नष्ट कर देंगे तो फिर यह वाराणसी नहीं होगा। वाराणसी में अनेक छोटे-छोटे प्राचीन मंदिर हैं, जिनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्त्व है जो पुनर्निर्माण योजना की भेंट चढ़ रहे हैं। माना जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब मंदिरों और मूर्तियों को ध्वस्त करना आरंभ किया तो काशीवासियों ने उनको अपने घरों के अंदर छिपा लिया था। चूंकि पुनर्निर्माण योजना में आसपास के मकानों को हटाना और गंगा तट तक सीधे रास्ता बनाना शामिल है इसलिए आरंभ में वहां केवल विध्वंस ही दिखता है। आलोचनाओं और प्रखर विरोधों पर बिना कुछ बोले मोदी अपनी कार्ययोजना पर अडिग रहे और अंतत- बहुत सारी बाधाएं हटने के बाद शिलान्यास भी कर दिया। प्रश्न है कि इसे किस तरह देखा जाए? एक ओर विरोधी हैं तो दूसरी ओर प्रवासी सम्मेलन में आए भारतवंशियों की प्रतिक्रियाएं, जिनके उद्गार बता रहे थे कि उन्होंने सपने में नहीं सोचा था कि इस तरह का वाराणसी उन्हें देखने को मिलेगा? कोई भी वारणसी में जाकर बदलाव देख सकता है। स्टेशन या हवाई अड्डे से ही परिवर्तन दिखने लगता है। काशीवासी स्मार्ट सिटी बनने के साथ नगर की आध्यामिकता, सांस्कृतिक-पौराणिक धरोहरों और स्मारकों के संरक्षण-संवर्धन भी चाहते हैं और स्वच्छता और पर्यावरण के पैमाने पर भी इसे एक मानक बनाने का सपना रखते हैं। साफ है कि कॉरिडोर निर्माण के साथ विश्वनाथ मंदिर को भव्य रूप मिलेगा, मंदिर से गंगा तक जाने और गंगा से स्नान कर मंदिर आना आसान हो जाएगा। शिलान्यास के बाद मोदी ने कहा कि सालों बाद बाबा विश्वनाथ को मुक्ति मिली है। जो उन मकानों को ही वाराणसी की संस्कृति मानते रहे हैं, वे भी गलत नहीं हैं, पर इसमें बदलाव के बगैर उसे विश्व के महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्थल में बदलना संभव ही नहीं। जिन भवनों के अधिग्रहण और ध्वंस को विरोधी वाराणसी की पहचान का ध्वंस कहते हैं, वही सरकार के लिए सांस्कृतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण शहरों के पुनर्निर्माण प्रबंधन की मिसाल है। एक बार पुनर्रचना की वृहत्तर योजना और कायरे पर संक्षिप्त दृष्टि डालना जरूरी है। काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को सुगम दर्शन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम की रचना की जा रही है। मंदिर सीधे गंगा नदी से जुड़ेगा। वर्तमान परियोजना का कुल क्षेत्रफल 39310.00 वर्ग मीटर है, जिसके अंतर्गत कुल 296 आवासीय, व्यावसायिक, सेवईत, न्यास भवने हैं। अब तक करीब 240 भवन खरीदे गए, जिनको गिराने के बाद लगभग 21505.92 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध हुआ है। 500 से ज्यादा परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है। इसके लिए योगी सरकार ने कुछ उपयुक्त अधिकारियों को वहां नियुक्त किया और कॉरिडोर निर्माण के लिए 600 करोड़ रु पये भी दिया। अब प्रश्न इन भवनों में स्थित मंदिरों का है। भवनों को गिराने के दौरान 41 प्राचीन मंदिर पाए गए हैं, जिनका उल्लेख धार्मिक पुस्तकों में है। ये सभी मंदिर काशी के प्राचीन धरोहर हैं। इन मंदिरों को भी जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण परियोजना का अंग बनाया गया है। ये सारे मंदिर लोगों के दर्शन के लिए उनके पुराने नामों से उपलब्ध रहेंगे। आलोचक जो भी कहें अब वे मंदिर श्रद्धालुओं के लिए ज्यादा आकर्षक ढंग से सुलभ होंगे। परियोजना में काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण का विस्तार कर इसमें विशाल द्वार बनाए जाएंगे और एक मंदिर चौक का निर्माण किया जाएगा। इसके दोनों ओर विश्रामालय, संग्रहालय, वैदिक केंद्र, वाचनालय, दर्शनार्थी सुविधा केंद्र, व्यावसायिक केंद्र, पुलिस एवं प्रशासनिक भवन, वृद्ध एवं दिव्यांग के लिए एक्सीलेटर एवं मोक्ष भवन इत्यादि निर्मित किए जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह कि कॉरिडोर निर्माण के बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जकड़न से मुक्त होगा और वहां आने वाले करोड़ों देशी-विदेशी श्रद्धालुओं का आवागमन, वास एवं दर्शन-पूजन पहले की अपेक्षा सुगम होगा। यह एक उदाहरण होगा कि हम अपने धार्मिक स्थलों के सांस्कृतिक स्वरूप को बनाए रखते हुए किस तरह उसका आवश्यकता के अनुरूप कायाकल्प कर सकते हैं। वाराणसी की उग्रह तस्वीरों से एक-एक स्थान का अध्ययन कर पूरे शहर और आसपास के लिए योजनाएं बनीं, उनमें ही यह परियोजना भी शामिल है। आलोचनाओं के राजनीतिक जोखिम को समझते हुए भी साकार करने के लिए काम करते रहना साहस का विषय है। विरोध हर बदलाव का होता है किंतु बदलाव जरूरी हो तो उसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी होती है।

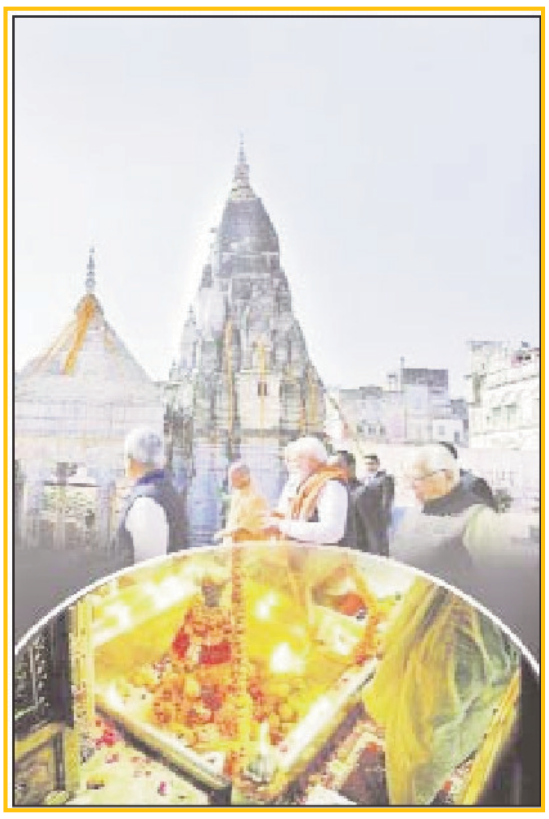

## आज का राशीफल

**मेष** आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।

**वृषभ** पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। रुपये पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। ससुराल पक्ष से तनाव मिलेगा।

**मिथुन** जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किसी रिश्तेदार के कारण तनाव मिल सकता है। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

**कर्क** आर्थिक योजना फलीभूत होगी। धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। अनावश्यक व्यय से मन अशान्त रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

**सिंह** राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। व्यवसायिक व पारिवारिक योजना सफल रहेगी। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। प्रियजन भेंट संभव।

**कन्या** संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। नए अनुबन्ध प्राप्त होंगे। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। व्यर्थ की भागदौड़ भी रहेगी।

**तुला** जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। आमोद-प्रमोद के साधनों में वृद्धि होगी।

**वृश्चिक** व्यावसायिक योजना सफल होगी। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

**धनु** पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी रिश्तेदार के कारण तनाव मिल सकता है। विरोधियों का पराभव होगा। वाद विवाद की स्थिति आपके हित में न होगी।

**मकर** दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक कष्टों का सामना करना पड़ेगा।

**कुम्भ** बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। शासन सत्ता से तनाव मिलेगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी।

**मीन** गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। खान-पान में संयम रखें। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

# अपना काम करें चुपचाप

- डॉ. दीपक आचार्य

हर इंसान पूरी जिन्दगी किसी एक लक्ष्य को केन्द्र में रखकर अपने व्यक्तित्व को गढ़ता है और उसी के अनुरूप वह अपने चरित्र, स्वभाव और व्यवहार का निर्धारण करते हुए आगे बढ़ता है। लक्ष्य के मामले में साफ-साफ कहा गया है कि यह अपने व्यक्तित्व का सर्वांग विकास कर आत्म प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। यह प्रतिष्ठा ऐसी होनी चाहिए कि कोई इसे अस्वीकार करने का साहस नहीं कर पाए। यह प्रतिष्ठा दिलों में होनी चाहिए न कि लोकप्रियता के पैमाने तय करने के लिए भीड़ और भीड़ से बुलवायी जाने वाली जय-जयकार जैसी या पराये माध्यमों से अपने आपको स्वयंभू या अधीश्वर मनवाने जैसी। जब किसी को दिल से स्वीकारा जाता है तभी वह प्रतिष्ठित कहा जा सकता है अन्यथा लोभ-लालच, तरह-तरह के प्रलोभन या कि भय और दबावों के जरिये कोई किसी से कुछ भी करा सकता है चाहे वह आदमियों का छोटा समूह हो अथवा बड़ी से बड़ी भीड़ का रेला। आजकल आदमी सिद्धान्तों, नीति और धर्म के अनुरूप व्यवहार करने की बजाय दूसरे रास्तों पर ज्यादा यकीन करता है। कारण यह है कि ये रास्ते आसान हैं और ज्यादा कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, न सच्चाई का पुट होता है न स्वाभिमान का, इसलिए इसे स्वीकारते हुए सब कुछ कर लेना न केवल निरापद है बल्कि समय साध्य भी नहीं है। आम तौर पर इंसान अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति सतर्क होता है और मानस बनाकर उस दिशा में आगे बढ़ भी जाता है लेकिन बाहरी चकाचौंध, क्षणिक सुख और भौतिक विलासिता एवं उन्मुक्त भोगों में रमे हुए लोगों को देखता है, तब मान लेता है कि यही संसार बड़ा लक्ष्य है। ऐसे में वह पटरी से उतर कर भटक जाता है। इस अवस्था में वह न अपने लक्ष्य का रह पाता है, न बाहर की चकाचौंध का। लगभग इसी स्थिति में आकर बहुत सारे लोग फिसलने लगते हैं। और एक बार जो कोई भी, किसी भी कारण से फिसल जाता है, उसकी जिन्दगी में फिसलन एक हिस्सा हो जाती है। केवल लक्ष्य के प्रति नैष्ठिक समर्पण रखने वाले और दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति ही संकल्प के धनी हो सकते हैं जो न झँझावातों में फंसते हैं, न किसी विलासी चकाचौंध की ओर निगाह डालते हैं। और वास्तव में ये ही लोग जीवन लक्ष्य की परिपूर्णता का महा आनंद और अमरत्व पाने में इस तरह आशातीत सफल हो जाते हैं कि सदियों तक इन्हें आदर-सम्मान और श्रद्धा से याद रखा जाता है। मार्ग कोई सा चुनें वह चाहे लम्बा हो, पर होना चाहिए शुचिता भरा, लोक कल्याण से परिपूर्ण और समाज के लिए हितकारी। बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश तो करते हैं, परिश्रम भी खूब करते हैं, समय भी देते हैं लेकिन बीच में कहीं किसी चकाचौंध भरे व्यक्तित्व को देख लेते हैं तब भ्रमित हो जाते हैं। कच्चे संकल्पों वाले लोगों की यही सबसे बड़ी समस्या है। मवेशी जिस तरह चारा-घास देख कर उस तरफ रूख कर लेते हैं, उसी तरह ये लोग भी सुनहरे ख्वाबों और चकाचौंध भरे जंगलों में भटक जाते हैं। कई बार जब ये लोग भ्रष्ट, रिश्वतखोरों और दलालों के वैभव को देखते हैं, उनकी जमीन-जायदाद और भव्य प्रासाद, फॉर्म हाउस, लक्ज़री वाहनों और तमाम प्रकार के भोग-विलासों को देखते हैं तब इनका मन विचलित हो जाता है। यहीं से इनकी जिन्दगी के लक्ष्यों का या तो विखण्डन हो जाता है अथवा मार्गान्तरण। यह संक्रमण काल अधिकांश लोगों की जिन्दगी में आता है। जो संभल जाते हैं वे तर जाते हैं और जो मोह ग्रस्त हो जाते हैं वे वहीं अटक कर रह जाते हैं, इनकी जिन्दगी त्रिशंकु होकर रह जाती है जहाँ वे न घर के रह पाते हैं, न घाट के। इस संक्रामक स्थिति से बचने के लिए यह जरूरी है कि अपने लक्ष्य के पति समर्पित रहें, दाँये-बाँये न देखें, किसी भी तरह की चकाचौंध और विलासिता या विलासी-वैभवशाली लोगों की ओर आसक्त न हों, क्योंकि यह सब कुछ जिस बुनियाद पर टिका होता है उसमें अधिकतर मामलों में भ्रष्टाचार ही प्रधान कारक होता है जिसका कुछ समय तक तो आनंद पाया जा सकता है लेकिन भविष्य कभी ठीक नहीं होता। देर-सबेर चोरी, बेईमानी, कमीशनखोरी और दलाली पर टिका महल गिरता ही गिरता है। इसका संबंध हमारे संचित पुण्य से है। जब तक पुण्य रहेंगे तब तक सब ठीक-ठाक चलता रहेगा, इसके बाद उल्टी गिनती शुरू होनी ही है। अपने लक्ष्यों के सिवा कहीं भी दूसरी तरफ झाँकने का परिणाम हमेशा खराब ही रहता है। बार-बार लक्ष्य बदलना भी ठीक नहीं होता। जीवन का अपनी पसंद और कल्पनाओं का अपना मार्ग चुनें और उसी दिशा में आगे बढ़ते रहें, लक्ष्य एक हो, नेक हो। अपनी मौलिकताओं को आकार देने के लिए अपनाया जाने वाला मार्ग हमेशा आशातीत सफलता देता है और कालजयी कीर्ति प्रदान करता है। जो औरों में दिखाई दे रहा है वह वास्तविक न होकर छद्म नींवों पर टिका है। किसी ओर की लोकप्रियता और वैभव को अपना ध्येय न मानें, अपने मार्ग पर निरन्तर बढ़ते रहें। अपना रास्ता खुद तैयार करें, अपनी मंजिल अपने आप प्राप्त हो जाएगी। समय लग सकता है।

# अच्छे शिक्षण की बजाय पदों को महत्व देने के खतरे

एस. गिरिधर सीओओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन

हमारे कार्यालयों और संस्थानों में पद-क्रम में ऊंच-नीच की जकड़न नई नहीं है। इस जकड़न से मेरा सीधा परिचय कई साल पहले हो गया था। दरअसल, एक राज्य में परीक्षाओं में सुधार का एक प्रशंसनीय प्रस्ताव लाया गया, जिसमें महज रट्टेबाजी की जांच करने वाले सवालों की जगह अवधारणात्मक सवाल रखने की बात की गई। दो दिन की कार्यशाला का आयोजन भी तय हुआ, जिसमें विद्वान शिक्षाविदों को बुलाया गया, ताकि वे अपनी विशेषज्ञता सबसे साझा कर सकें। आयोजन से कुछ ही दिनों पहले विभाग के निदेशक को पता चला कि कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में वरिष्ठ अधिकारी व मंत्री भी आएंगे। उन्होंने आयोजन की तैयारी को दूसरी ही दिशा में मोड़ दिया। अचानक सबका ध्यान कार्यशाला के अकादमिक पहलुओं से हटकर बेमतलब के प्रोटोकॉल और विभागीय कर्मकांडों पर केंद्रित हो गया। जो समय शैक्षणिक चर्चा में लगाया जा सकता था, वह इस आयोजन की तनावपूर्ण औपचारिकताओं में निकल गया। विभाग के निदेशक महोदय को टोकने की परंपरा ही नहीं थी, क्योंकि वह ऊंचे पद पर बैठे थे, और कनिष्ठ अधिकारी या कर्मचारी उन्हें समझाने का साहस भला कैसे कर सकते थे? एक ऐसे तंत्र में, जहां ऊंचे पदों के प्रति अर्थहीन श्रद्धा दिखाने का चलन है, ऐसे कई बेहतरीन शिक्षक हैं, जो दासता की इस संस्कृति के दमकते अपवाद हैं। मैंने इन शिक्षकों के बेहतरीन गुणों, नेतृत्व क्षमता, कल्पनाशील शिक्षण आदि के बारे में लिखा है, लेकिन आज मैं आपका ध्यान कुछ शिक्षकों में मौजूद एक और सराहनीय गुण की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। इसे मैं कहूंगा, 'अधिकारियों का सामना करने का आत्म-विश्वास'। इस गुण की जांच के लिए मेरे पास एक निजी संकेतक है- जब कोई निरीक्षक या अधिकारी स्कूलों में जाते हैं, तो ज्यादातर हेड टीचर तुरंत खड़े हो जाएंगे और अपनी कुरसी उनके बैठने के लिए खाली कर देंगे, क्योंकि यह 'शिष्टाचार' इस व्यवस्था की संस्कृति का हिस्सा है। अगर ऐसे दमघोंटू माहौल में मुझे ऐसे हेड टीचर मिलते हैं, जो इस संस्कृति को नहीं मानते और खुद को अपने पद से कमतर नहीं आंकते, तो मैं इसे उनके आत्म-विश्वास का, स्वतंत्र चेतना का संकेतक मानता हूं। बेशक मैं सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र से मिसालें दे रहा हूं, लेकिन ऊंचे पदों के प्रति दासता का भाव हमारे शासन तंत्र और जीवन के हर आयाम में ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। अगर किसी विभाग का मुखिया महज हफ्ते भर पहले ही विभाग में आया है, फिर भी वह विभागीय मसले पर पूरे अधिकार से बोलेगा और बाकी लोग चुप रहेंगे। समय के साथ पद से मिली ताकत को दिखाने के तरीके बहुत बारीक हो गए हैं। मैंने नौकरशाहों की अध्यक्षता में हुई बैठकों में देखा है कि मेज के इर्द-गिर्द कुरसियों के दो घेरे होते हैं। एक अंदरूनी घेरा, जो बैठक की मेज से लगा होता है और एक बाहरी घेरा, जिसमें कुरसियां दीवार से लगी होती हैं। भले ही बैठक में ज्यादातर जानकारी जूनियर को देनी हो, पर उसे अपनी बात बाहरी घेरे से ही करनी होगी। बाकी सदस्य, भले ही उनको कुछ नहीं कहना हो, अंदर के घेरे में बैठे रहेंगे, क्योंकि वे वरिष्ठ हैं। ऐसे गुलामी भरे माहौल में मुझे छोटे-छोटे जमीनी बदलाव भी उम्मीद से भर देते हैं। मुझे ऐसे गजब के शिक्षक देखने को मिले हैं, जिनमें सत्ता के सामने नहीं झुकने का नायाब गुण है। निरर्थक दासता का कीड़ा शासन तंत्र को खोखला कर देता है, पर ऐसी संस्कृति का असर शिक्षा क्षेत्र में सबसे खतरनाक होता है। अगर शिक्षा की संस्कृति में सवाल उठाने की गुंजाइश नहीं होगी, तो शिक्षक व शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों में सोचने, आजादी व ईमानदारी के साथ जीने वाले तार्किक और सामाजिक तौर पर सचेत नागरिक बनने की संभावनाएं कैसे विकसित कर सकेंगे? यही वह वजह है कि अच्छे शिक्षकों में आजादी व सच्चाई के ये चिह्न जरूरी हैं। अक्सर देखा गया है कि अच्छा बदलाव धीमा और कठिन होता है, पर जैसे-जैसे ज्यादातर लोग अच्छे रास्ते पर चलेंगे, हमारे सार्वजनिक जीवन में गहरे पैठी पद-क्रम की ऊंच-नीच की कमजोरी घटती चली जाएगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

# आरबीआई बोर्ड ने मोदी सरकार को दी थी चेतावनी, नोटबंदी से काले धन पर नहीं लगेगी रोक

**नई दिल्ली।**

8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा लिए गए नोटबंदी के फैसले से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कई बोर्ड सदस्य राजी नहीं थे। नोटबंदी को लागू करने से पहले छह महीने तक लगातार सरकार और आरबीआई के बीच काफी मंथन हुआ था। आरबीआई के निदेशकों ने सरकार को तभी चेता दिया था कि इससे कालेधन पर रोक नहीं लगेगी। दरअसल, सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोट प्रचलन से बाहर करने के पीछे बड़ा तर्क दिया था कि इससे कालेधन पर नकेल कसेगी। साथ ही नकली मुद्रा पकड़ में आएगी और ई-पेमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। पर जानकारों और आंकड़ों की मानें तो कालेधन पर लगाम लगाने में सरकार का यह निर्णय नाकाफी रहा। आरबीआई के निदेशकों व सरकार के बीच नोटबंदी की घोषणा होने से पहले तीन घंटे तक मंथन हुआ था। इस बैठक में आरबीआई के निदेशकों ने सरकार से कहा था कि ज्यादातर कालाधन नकद न होकर के रियल एस्टेट और सोने में निवेश के तौर पर लगाया गया है। इससे इन पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही 400 करोड़ रुपए के बड़े नोटों का प्रचलन होने को भी आरबीआई के निदेशकों ने ज्यादा बड़ा नहीं माना था। निदेशकों का तर्क था कि अर्थव्यवस्था के बढ़ने के कारण इतने मूल्य के बड़े नोटों का प्रचलन अच्छा कारक है। नोटबंदी से पहले आरबीआई के निदेशकों ने सरकार को चेतावनी दी थी, कि इसको लागू करने से थोड़े समय के लिए देश की विकास दर पर असर पड़ेगा, हालांकि बाद में उन्होंने नोटबंदी को अच्छा बताया था। इन सब तर्कों के बावजूद आरबीआई के बोर्ड ने नोटबंदी को लागू करने की मंजूरी दे दी थी। इसका समर्थन करने का प्रस्ताव आरबीआई के एक डिप्टी गवर्नर ने वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए एक नोट के बाद किया था। इस नोट में सरकार की तरफ से तर्क था कि 2011-12 से लेकर 2015-16 के बीच अर्थव्यवस्था 30 फीसदी की दर से आगे बढ़ी है।

# पीएफ अकाउंट धारकों के लिए ईपीएफओ ला रहा खास सुविधा मिलेगा फायदा

**नई दिल्ली।**

एक जगह से नौकरी छोड़ने के बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन करने पर अकसर श्रमिकों के लिए अपने पीएफ को दूसरी जगह ट्रांसफर करवाने के लिए कई कुछ करना पड़ता है। लेकिन आने वाले दिनों में ये काम भी आसान हो जाएगा। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पीएफ धारकों के लिए एक खास सुविधा लाने जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों को अगले वित्त वर्ष से नौकरी बदलने पर ईपीएफ हस्तांतरित करने के लिए आवेदन नहीं करना होगा। श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार, यह ईपीएफ के हस्तांतरण की प्रक्रिया अपने आप हो जाएगी। बता दें कि ईपीएफओ के सदस्यों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) रखने के बाद भी अमाउंट के ट्रांसफर के लिए अलग से अनुरोध करना पड़ता है। अधिकारी के मुताबिक ईपीएफओ ने पेपरलेस वर्क के लिए लगातार काम कर रहा है। अभी 80 प्रतिशत वर्क ऑनलाइन हो रहे हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में नौकरी बदलने पर पीएफ अमाउंट का ऑटोमेटिक ट्रांसफर महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ को हर साल ईपीएफ हस्तांतरण के करीब 8 लाख आवेदन मिलते हैं। श्रम मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि जैसे ही नए नियोक्ता मासिक ईपीएफ रिटर्न दायर करेंगे जिसमें

नये कर्मचारी का यूएएन भी शामिल होगा। वैसे ही पहले के ईपीएफ योगदान और उसपर मिले ब्याज का ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। सभी खाताधारकों के लिए यह सुविधा अगले वित्त वर्ष में किसी समय शुरू हो सकती है।

# लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमतें

**बिजनेस डेस्क।**

आम चुनाव की घोषणा के बाद पेट्रोल-डीजल के दामों में फिर से तेजी देखने को मिल रही है। पेट्रोल-डीजल के दामों को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश सऊदी अरब से कच्चे तेल की दरों को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले एक महीने में 2 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा बढ़ चुके हैं। इसके पीछे मुख्य रूप से अमेरिका और चीन के बीच व्यापार मोर्चे पर टकराव समाप्त होने की उम्मीद के साथ-साथ तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के सहयोगी रूस द्वारा तेल आपूर्ति में कटौती बढ़ाने की घोषणा शामिल है। दिल्ली में आज पेट्रोल 6 पैसे महंगा हुआ जबकि डीजल के दाम में कटौती हुई है।

दिल्ली में आज पेट्रोल 72.46 रुपए लीटर मिल रहा है जबकि डीजल 67.44 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ौतरी देखी गई है। सोमवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल 0.46 फीसदी की वृद्धि के साथ 66.04 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। क्रूड भी 0.54 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 56.37 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।

# फेसबुक मैसेंजर पर मिला बग, लीक कर रहा था आपका पर्सनल डाटा और चैट्स

**नई दिल्ली ।**

अगर आप फेसबुक मैसेंजर का इस्तेमाल करते है तो आपको सावधान रहने की जरुरत है। दरअसल, एप में एक बग पाया गया है जो यूजर के डाटा को एक्सेस कर सकता है। इस बग के कारण वेबसाइट्स यूजर का डाटा एक्सेस कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार यह बग फेसबुक द्वारा फिक्स कर दिया गया है। इस बग के बारे में जानकारी देते हुए साइबर सिक्योंरिटी फर्म ने बताया कि इस बग के चलते यूजर्स का पर्सनल डेटा और चैट्स सेफ नहीं थे। बग से जुड़ी जानकारी शेयर करते हुए फर्म ने लिखा, जब करेंट यूजर किसी खास यूजर के कॉन्टैक्ट में नहीं होता तो आईफ्रेम काउंट तीन पर पहुंचता है और कुछ मिलीसेकेंड्स के लिए हमेशा नीचे जाता है। इसकी मदद से कोई भी अटैकर फुल और इंपटी स्टेट्स में अंतर कर सकता था। इसकी मदद से कोई भी रिमोटली चेक कर सकता था कि यूजर किसके साथ चैटिंग करता रहा है ।

या कभी चैटिंग की है। यह यूजर की प्रिवेसी के लिए सीधा खतरा था। हालांकि अच्छी बात यह है कि गड़बड़ मोबाइल ऐप पर नहीं थी और मेसेंजर के वेब क्लाइंट पर ही रिपोर्ट की गई थी, जिसे फेसबुक ने फिक्स कर दिया है।

## संक्षिप्त समाचार

### किसान सम्मान निधि के तहत 2.6 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक 5,215 करोड़ रुपए का अंतरण

**नई दिल्ली।** प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 2.6 करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसानों को 5,215 करोड़ रुपए का अंतरण किया गया। पिछले महीने 2019-20 के अंतरिम बजट में सरकार ने इन किसानों को एक निश्चित न्यूनतम आय मुहैया कराने के लिए इस योजना की घोषणा की थी। आम चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए की इस योजना की घोषणा की थी। इसके तहत देश में दो हेक्टेयर से कम जोत वाले करीब 12 करोड़ किसानों को तीन किस्तों में 6,000 रुपए की न्यूनतम वार्षिक आय मुहैया कराई जानी है। अंतरिम बजट में सरकार ने इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके तहत मार्च के अंत तक किसानों को 2,000 रुपए की पहली किस्त पहुंचानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की आधिकारिक शुरुआत 24 फरवरी को गोरखपुर में की थी। रविवार को प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा कि इस योजना की घोषणा के 37 दिन के भीतर 2.6 करोड़ से अधिक छोटे एवं सीमांत किसानों को अब तक 5,215 करोड़ रुपए उनके बैंक खाते में अंतरित किए गए हैं।

### कार, गहना खरीदना हो सकता है सस्ता, महंगे सामान पर जीएसटी के लिए अलग रखी जाएगी आयकर वसूली

**बिजनेस डेस्क।** केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा - शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि जीएसटी देनदारी की गणना के समय स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) की राशि को उत्पाद के मूल्य से अलग रखा जाएगा। इससे महंगी कार और आभूषण खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। आयकर अधिनियम के तहत , 10 लाख रुपए से ऊपर के वाहन ,5 लाख रुपए से अधिक के आभूषण और दो लाख रुपए से ज्यादा का सोना - चांदी खरीदने पर स्रोत पर कर वसूली (टीसीएस) एक प्रतिशत लगता है। अन्य चीजों की खरीद पर भी अलग-अलग दरों से टीसीएस लगता है। सीबीआईसी ने परिपत्र में कहा कि वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) देयता की गणना करते समय टीसीएस राशि को माल के मूल्य से अलग रखा जाएगा। इससे पहले दिसंबर में बोर्ड ने कहा था कि आयकर अधिनियम के तहत जिन उत्पादों पर स्रोत पर कर वसूली लागू होती है उन पर जीएसटी की गणना के दौरान टीसीएस राशि को भी इसमें शामिल किया जाएगा। विभिन्न हितधारकों से मिली प्रतिक्रिया और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से बातचीत के बाद सीबीआईसी ने फैसला किया है कि जीएसटी लगाने के उद्देश्य से माल का मूल्यांकन करने के समय टीसीएस राशि को अलग रखा जाएगा। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है कि टीसीएस माल पर कर नहीं है बल्कि विक्रेता की माल की बिक्री से होने वाली संभावित आय पर लगने वाला अंतरिम शुल्क है।

### दो युवकों ने फेसबुक को पहुंचाया 75 हजार पाउंड का नुकसान, 60 हजार यूजर्स का डाटा किया लीक

**सैन फ्रांसिस्को ।** यूक्रेन के रहने वाले दो युवकों ने एक ऑनलाइन क्विज के माध्यम से 60 हजार से ज्यादा फेसबुक यूजर्स को ब्राउजर स्थापित करने का लालच लेकर उनका प्रोफाइल डेटा लीक कर दिया। कंपनी ने दायर अपने मुकदमे में इस बात की जानकारी दी। द डेली बीस्ट ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट में बताया कि एंड्रयू गोब्रेकोव और ग्लेब स्लक्रेस्की ने फेसबुक न्यूज फीड पर अपने खुद के विज्ञापन दिखाने के लिए ब्राउजर एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया। फेसबुक ने शुक्रवार को दायर अपने मुकदमे में बताया कि कीव में रहने वाले उद्यमियों ने कैलिफोर्निया और एंटी हैकिंग कानूनों का उल्लंघन किया है और इनके ऊपर फेसबुक के नियमों का उल्लंघन करने के लिए मुकादमा चलाया जाएगा। इसी के साथ कंपनी ने ये भी आरोप लगाया कि इन आरोपियों ने खासतौर पर रूसी भाषी लोगों को टारगेट किया है। कंपनी ने लिखा है कि एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के दौरान एप यूजर्स ने खुद के ब्राउजर के साथ समझौता किया। एक्सटेंशन को इस तरह तैयार किया गया था कि जब एप यूजर्स फेसबुक या अन्य किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर जाएं तो उस दौरान उनकी जानकारी लीक हो जाए और उन्हें अनाधिकृत विज्ञापन नजर आएं। दोनों अभियुक्त वेब सन ग्रुप नामक कंपनी से ताल्लुक रखते हैं। कंपनी ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि कुल मिलाकर इन दोनों अभियुक्तों ने फेसबुक यूजर्स द्वारा लगभग 63 हजार ब्राउजरों का इस्तेमाल किया और फेसबुक को 75 हजार पाउंड का नुकसान पहुंचाया। कंपनी ने इस तरह की चीजों को जड़ से खत्म करने की बात भी कही है। हाल ही में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक यूजर्स के लिए प्राइवेसी फोकस को ध्यान में रखते हुए काम करने के लिए एक नोट पोस्ट किया था।

# कच्चे तेल के दाम बढ़ने पर भारत ने सऊदी अरब से जताई चिंता

**नई दिल्ली ।** पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री खालिद अल-फलीह के साथ बैठक में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से घरेलू तेल की कीमतों में पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई। धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अल फलीह से बात करते हुए पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपोक और अन्य तेल निर्यातकों द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई में कटौती के मद्देनजर भारत को कच्चे तेल और एलपीजी की निर्बाध सप्लाई को लेकर बातचीत की। अल फलीह की यात्रा सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की इस साल फरवरी में भारत दौरे के बाद पहली यात्रा है। बयान में ये भी कहा गया कि दोनों मंत्रियों ने भूराजनीतिक घटनाक्रमों का वैश्विक तेल बाजार पर प्रभाव को लेकर भी चर्चा की। इसी के साथ इन दोनों मंत्रियों ने भारत के तेल और गैस क्षेत्र में सऊदी के निवेश प्रस्तावों की समीक्षा की, जिसमें महाराष्ट्र में वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी संयुक्त उपक्रम और पेट्रोकेमिलकल प्रोजेक्ट शामिल है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 44 अरब डॉलर है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी होगी। दोनों नेताओं ने भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियन रिजर्व (एसपीआर) प्रोग्राम में सऊदी अरब की भागीदारी पर भी बात की।

# भारत में जल्द ही अमेजॉन प्राइम पर दिख सकते हैं केबल टीवी चैनल्स

**नई दिल्ली।**

केबल टीवी चैनल्स और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज दो अलग-अलग इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें भारतीय महानगरों में पकड़ बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। अब एक नई जानकारी के मुताबिक भारतीय बाजार के टॉप स्ट्रीमिंग प्लेयर्स में से एक अमेजॉन अपने अमेजॉन प्राइम वीडियो में ज़ूङ्क चैनल्स को मिक्स कर सकता है यानी कंपनी केबल टीवी चैनल्स को अपने अमेजॉन प्राइम वीडियो सर्विसेज में ला सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फीचर कोई नया फीचर नहीं है, अमेजॉन इस सर्विस को पहले से ही यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और जापान जैसे देशों में उपलब्ध करा रहा है। द हिंदू बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी जल्द ही इस सर्विस को भारतीय बाजार में लाने की तैयारी में है। फिलहाल इसकी लॉन्चिंग के लिए कोई निश्चित तारीख तय नहीं की गई है लेकिन उम्मीद है कि आने वाले महीनों में इस सर्विस को भारतीय बाजार में लाया जाए। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेजॉन चुनिंदा बाजारों में ट्रेडिशनल टीवी चैनल्स को सब्सक्राइब करने की सुविधा देता है। इन टीवी चैनलों में के नाम शामिल हैं। रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो यूजर्स अमेजन को सब्सक्रिप्शन फीस देना होगा, जिसे कंपनी केबल चैनल्स या सैटेलाइट प्रोवाइडर को देगी। इस सिस्टम के तहत टीवी चैनल्स यूजर्स के लिए अमेजॉन प्राइम वीडियो में ही जुड़ जाएंगे। प्राइम वीडियो के लिए इंटरनेशनल ओरिजिनल्स के हेड, जेम्स फेरल कहते हैं कि ये सर्विस ने वास्तव में काफी अच्छा किया है। साथ ही ये भी कहा है कि ये जल्द ही भारत आ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस फीचर का पाने के लिए यूजर्स के पास प्राइम सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। इस फीचर के तहत ग्राहक अपनी पसंद के टीवी चैनल को सेलेक्ट कर पाएंगे और उसे सब्सक्राइब कर पाएंगे।

# सबसे ज्यादा खारिज हुए भारतीय आईटी कंपनियों के एच-1बी वीजा बढ़ाने के आवेदन

**बेंगलुरु।**

साल 2018 के दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कॉग्निजेंट और इन्फोसिस के एच-1बी वीजा एक्सटेंशन के अनुरोध सबसे ज्यादा खारिज हुए। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के इससे जुड़ी प्रक्रिया को सख्त बनाने के कारण हुआ। माना जा रहा है कि अमेरिकी टेक्नॉलजी कंपनियों को तरजीह देने के लिए ऐसा किया गया। इन्फोसिस और टीसीएस पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ा। इन्फोसिस के 2042 आवेदन खारिज किए गए, वहीं टीसीएस के मामले में इनकी संख्या 1744 रही। ये आंकड़े एक अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज ने एच-1बी डेटा की एनालिसिस के बाद जुटाए हैं। अमेरिका में हेडक्वॉर्टर वाली और अपने अधिकतर कर्मचारी भारत में रखने वाली कॉग्निजेंट के 3548 आवेदन साल 2018 में खारिज हुए। यह किसी भी कंपनी के लिए सर्वाधिक संख्या रही। थिंक टैंक ने कहा कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट के अलावा टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक्नॉलजीज की अमेरिकी इकाइयों के खारिज हुए आवेदनों की संख्या टॉप 30 कंपनियों के ऐसे आवेदनों के करीब दो तिहाई पर रही। उसने यूएस सिटीजनशिप ऐंड इमिग्रेशन सर्विसेज की ओर से पेश आंकड़ों के विश्लेषण के बाद यह बात कही। इन छह कंपनियों को महज 16 प्रतिशत यानी 2145 एच-1बी वीजा परमिट मिले। साल 2018 में अकेले अमेजॉन को 2399 वीजा परमिट मिले। एच-1बी वीजा का उपयोग अधिकतर टेक्नॉलजी प्रफेशनल्स करते हैं। ये शुरू में तीन साल के लिए दिए जाते हैं। इन्हें और तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। थिंक टैंक ने 6 मार्च को जारी अपनी स्टडी में कहा कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और एप्पल सरीखी बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने साल 2018 में अपनी एच-1बी वीजा वर्कफोर्स बढ़ाई, वहीं कॉग्निजेंट, टाटा और इन्फोसिस सरीखी बड़ी भारतीय कंपनियों के मामले में वीजा परमिट घटा दिया गया। इस मामले में टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और कॉग्निजेंट ने कमेंट करने से मना कर दिया। एचसीएल टेक्नॉलजीज से संपर्क नहीं किया जा सका। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ व्यापार के मसले सुलझाने के लिए उसने बहुत प्रयास किया है। भारत के साथ अमेरिकी ट्रेड डेफिसिट साल 2018 में घटकर 21.3 अरब डॉलर पर आ गया, जो साल 2017 में 22.9 अरब डॉलर पर था।

# फेम -2 के तहत अप्रैल महीने में मिलेगी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी

**बिजनेस डेस्क।** देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और को बढ़ावा देने के लिए पेश फेम - दो योजना के तहत अप्रैल महीने से 10 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को 20,000 रुपये और 35,000 चार पहिया वाहनों को डेढ लाख रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। इससे खरीदारों के लिए वाहन खरीदना सस्ता होगा। इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों के विनिर्माण और उनके तेजी से इस्तेमाल (फेम) के दूसरे चरण को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। कुल 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली यह योजना तीन वर्षों के लिए शुरू की जाएगी। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक , इसके तहत 7090 इलेक्ट्रिक बसों (कारखाने पर दो करोड़ रुपये मूल्य तक की) पर प्रति बस 50 लाख रुपये तक का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इसके अलावा , 5 लाख ई - रिक्शों में प्रत्येक को 50,000 रुपये का वित्तीय प्रोत्साहन देने की तैयारी है। अधिसूचना के मुताबिक कारखाने पर 15 लाख रुपये तक के 35,000 इलेक्ट्रिक कारों पर डेढ लाख रुपये की छूट मिलेगी जबकि 15 लाख रुपये मूल्य तक तक के 20,000 हाइब्रिड चौपहिया वाहनों पर 13,000 रुपए की वित्तीय मदद मिलेगी। वाहन उद्योग ने आम चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले फेम - दो योजना की घोषणा करने के सरकार के कदम की सराहना की है क्योंकि और देरी का मतलब है कि इस योजना की शुरुआत नई सरकार के गठन के बाद ही होती। सियाम के महानिदेशक विष्णु माथुर ने कहा कि यह सही समय पर दिया गया अवसर है क्योंकि फेम - एक और फेम दो के बीच कोई अंतराल नहीं है। फेम - दो योजना के तहत 2019-20 में 1,500 करोड़ रुपये, 2020-21 में 5,000 करोड़ और 2021-22 में 3,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। फेम1 में 800 करोड़ रुपये की सहायता दी गयी थी। इस तरह दूसरा चरण एक बड़ी उछाल है।

# लोकसभा चुनाव से बाजार में आएंगे कई हजार करोड़ रुपए, कारोबारियों की होगी बल्ले-बल्ले

**नई दिल्ली ।**

देश की 543 सीटों पर लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस घोषणा के बाद देश की सियासत पूरी तरह से गरमा गई है। सात चरणों में होने वाले इन चुनावों को लेकर विभिन्न प्रकार के अनुमानों का दौर शुरू हो गया है। अगर सियासत से इतर औद्योगिक अनुमान की बात करें तो इस लोकसभा चुनाव के दौरान बाजार में 15-16 हजार करोड़ रुपए आएंगे जोकि कई लोगों के लिए अच्छे रोजगार व कमाई का साधन बन सकते हैं। इस राशि से फूड, एफएमसीजी सेक्टर, गारमेंट, ट्रांसपोर्ट, मीडिया जैसे सेक्टर में भारी खर्च के साथ छोटे कारोबारियों को फायदा होने जा रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक हर उम्मीदवार को 70 लाख रुपये खर्च करना तय किया गया है। हर सीट पर अगर तीन से चार प्रत्याशियों के चुनाव लडने का अनुमान लगाया जाए तो एक सीट पर चुनाव प्रचार के लिए अनुमानत: कम से कम 3 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। अगर 543 सीटों का हिसाब लगाया जाए तो ये आंकड़ा कई हजार करोड़ में चला जाएगा। वैसे उम्मीदवार तय राशि से काफी अधिक राशि खर्च करते हैं। एसोचैम के मुताबिक चुनाव के दौरान उम्मीदवार की तरफ से किए जाने वाले खर्च का सटीक अनुमान लगाना कठिन है, ।

लेकिन ये उम्मीदवार औसतन 5-7 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। उनके अलावा जो छोटे-मोटे उम्मीदवार होते हैं, वे भी लाखों रुपए चुनाव में फूंक डालते हैं। उम्मीदवार की तरफ से होने वाले खर्च के अलावा सरकारी मशीनरी भी चुनाव के दौरान कई सौ करोड़ रुपये खर्च करती।

इस प्रकार आगामी लोक सभा चुनाव में कम से कम 15-16 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार की तरफ से होने वाले खर्च को जोड़ दिया जाए तो लोक सभा की हर सीट के लिए अधिकतम 4 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस हिसाब से 543 सीटों के लिए 2172 रुपए खर्च होंगे।

सूरत। सूरत महानगर पालिका मुगलीसराय में मनपा कमिश्नर के आफिस के बाहर नाराज बेलदारों ने किया प्रदर्शन।

## इथोपियन विमान दुर्घटना में एक ही परिवार के 6 गुजरातियों की मौत

सूरत। इथोपियन विमान दुर्घटना में गुजरात के मूल निवासी और वर्षों से कनाडा में स्थायी एक ही परिवार के दो बच्चों समेत छह लोगों की मौत हो गई। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से नैरोबी के लिए उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद इथोपियन एयरलाइंस का एक विमान रविवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

दक्षिण गुजरात के सूरत के मूल निवासी पन्नागेस वैद्य वर्षों से परिवार समेत कनाडा के टोरंटो में रह रहे थे। पन्नागेस वैद्य अपनी पत्नी हंसिनी वैद्य और कनाडा में रहतीं उनकी पुत्री कोशा, दामाद प्रतीक और उनकी दो पुत्रियों सफारी पार्क देखने के लिए इथोपियन एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान में जा रहे थे। उस दौरान विमान क्रेश हो गया। जिसमें पन्नागेस समेत परिवार के छह लोगों की मौत हो गई। सफारी पार्क देखने पन्नागेस के पुत्र मनन और उनका परिवार भी जानेवाला था। लेकिन किसी कारण वह नहीं जा सके और दुर्घटना का शिकार होने से बच गए। विमान दुर्घटना में मारे गए पन्नागेस वैद्य का दूसरा पुत्र मयंक अहमदाबाद में रहता है। पन्नागेस वैद्य की चचेरी बहन दिसी वोरा के मुताबिक 15 साल पहले पन्नागेस वैद्य वडोदरा के इलोरा पार्क में रहते थे। हांलाकि बाद में वह अहमदाबाद रहने चले गए। जहां से कनाडा के टोरन्टो में जाकर परिवार के साथ स्थायी हो गए। पन्नागेस एवं उनकी पत्नी हंसिनी वैद्य कनाडा नौकरी करते थे और पुत्र मनन के साथ रहते थे।

### ट्रक से 9.63 लाख का कपड़ा चोरी

सूरत। कोसंबा धामदोड गांव की सीमा में नॅशनल हाइवे पर स्थित एस्सार पेट्रोल पंप के सामने पार्क कपड़े से भरा ट्रक से चोरों ने 9.63 लाख की चोरी कर फरार हो गए।

### २८ मार्च से उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे

# गुजरात में ५१,७०९ बूथ पर २३ अप्रैल को मतदान

## दो सीट अनुसूचित जाति, चार सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित : २० सीटें जनरल केटेगरी की

अहमदाबाद। गुजरात में लोकसभा की २६ सीटों के लिए २३ अप्रैल को मतदान होगा तब गुजरात में भी इसे लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दौरान गुजरात में मतदान होगा। चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम घोषित करने के बाद गुजरात में मुख्य चुनाव अधिकारी एस मुरलीकृष्ण ने कहा कि आचारसंहिता लागू हो गई है। उम्मीदवार २८ मार्च से लेकर ४ अप्रैल के दौरान सुबह में ११ बजे से लेकर तीन बजे तक उम्मीदवारी फॉर्म भर सकते हैं। अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए दो सीट आरक्षित रखी गई है इसमें कच्छ और अहमदाबाद पश्चिम शामिल है जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई सीट में दाहोद, छोटाउदेपुर, बारडोली तथा वलसाड भी शामिल है। गुजरात में बाकी की २० सीटें जनरल केटेगरी में से उम्मीदवारों के लिए है। गुजरात में ५१७०९ मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा ही जिसमें से एक तिहाई शहरी क्षेत्रों में और दो तिहाई ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ८ मतदान केंद्रों पर १५०० से ज्यादा रजिस्टर्ड मतदाता है। ३८९५ मतदान केंद्रो पर ५०० से कम रजिस्टर्ड मतदाता है। ३१०५६ मतदान केंद्रों पर ५०० से १००० के बीच रजिस्टर्ड मतदाता है और १६७५० मतदान केंद्रों पर १००० और १५०० के बीच रजिस्टर्ड मतदाता है। गुजरात में २३ अप्रैल को मतदान आयोजित किया जाएगा। गुजरात में चुनाव के लिए अध्यादेश २८ मार्च को जारी किया जाएगा। उम्मीदवारी फॉर्म वापस लेने की अंतिम तारीख ४ से अप्रैल रहेगी। जांच की तारीख ५ अप्रैल रहेगी। उम्मीदवारी फॉर्म वापस लेने की अंतिम तारीख ८ अप्रैल होगी। सभी २६ सीट पर मतदान आयोजित किया जाएगा। लोकसभा चुनाव सात चरण में आयोजित किया जाएगा अब तीसरे चरण में गुजरात में चुनाव आयोजित किया जाएगा। चुनाव आयोग को यह दहशत सता रही है कि, गुजरात में चुनाव के दौरान मनी पावर का उपयोग हो सकता है। इस संभावना को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कई कदम उठाये है। फ्लाइंग टीमें भी लगायी जाएंगी। चेकपोस्ट पर जांच की जाएगी। गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी स्पर्धा होगी। गुजरात में २६ सीटों पर मत गिनती को लेकर सभी कदम उठाये गये हैं।

### हार्दिक राहुल गांधी की मौजूदगी में शामिल होंगे

# आज कांग्रेस जॉइन करेंगे हार्दिक पटेल : ट्वीट कर दी जानकारी

## देश और समाज की सेवा के मकसद से अपने इरादों को मूर्तरूप देने के लिए कांग्रेस जॉइन करने का निर्णय

अहमदाबाद। तमाम कयासों के बीच गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी जॉइन करने का ऐलान कर दिया है। हार्दिक ने अपने ऑफिशल ट्विटर अकाउंट से इस बात की जानकारी दी है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने ट्वीट किया, देश और समाज की सेवा के मकसद से अपने इरादों को मूर्तरूप देने के लिए मैंने १२ मार्च को राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इंडियन नैशनल कांग्रेस जॉइन करने का निर्णय लिया है। हार्दिक पटेल ने लिखा, मैं यह बताना चाहूंगा कि अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं है और पार्टी मुझे चुनावी राजनीति के मैदान में उतारती है तो मैं अपने दल के फैसले का पालन करूंगा। मैं भारत के सवा सौ करोड़ भारतवासियों के लिए यह कदम उठा रहा हूं। बता दें कि हार्दिक पटेल पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (PAAS) के संयोजक हैं। कोर समिति की सदस्य गीता पटेल ने पिछले दिनों बताया था, हार्दिक १२ मार्च को कांग्रेस में शामिल होंगे जब राहुल गांधी गुजरात में होंगे। हार्दिक को अहमदाबाद में आयोजित एक रैली में कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। पास ने हार्दिक को पार्टी में शामिल होने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि राजद्रोह के आरोपों से घिरे और जमानत पर चल रहे हार्दिक पटेल ने घोषणा की थी कि वह गुजरात से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे।

पाटीदार आंदोलन के अगुआ हार्दिक पटेल ने मंगलवार को गांधीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने का एलान किया है। हार्दिक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी खुद दी है। मंगलवार को ही गांधीनगर में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक प्रस्तावित है। बाद में एक रैली का भी आयोजन किया जाएगा। हार्दिक ने अप्रैल २०१५ में पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के बैनर तले विसनगर में अपना पहला आंदोलन किया था।

भाजपा विधायक के कार्यालय पर तोड़फोड़ और आगजनी के बाद हार्दिक चर्चा में आए थे। पिछले साल जुलाई में विसनगर कोर्ट ने इस मामले में उन्हें दो वर्ष की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की है जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। अगर सजा में राहत नहीं मिलती है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दो वर्ष की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ८ (३) के तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता।

### कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जन संकल्प रैली में हिस्सा लेंगे

# आज कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आयोजित होगी

## राहुल, मनमोहन व प्रियंका अडालज में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे : सोनिया गांधी भी उपस्थित

अहमदाबाद। आगामी लोकसभा चुनावों पर चर्चा के लिए गुजरात में मंगलवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक होगी। बैठक के बाद गांधीनगर के अडालज में एक रैली होगी जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति में आने के बाद पहली बार जनसभा को संबोधित कर सकती हैं। कांग्रेस की निर्णय लेने वाली शीर्ष इकाई सीडब्ल्यूसी की बैठक गुजरात में ५८ साल बाद हो रही है। इससे पहले १९६१ में बैठक हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल पार्टी में शामिल होंगे। पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख अमित चावड़ा ने बताया कि सरदार पटेल स्मृति भवन में बैठक के बाद राहुल गांधी, संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जन संकल्प रैली में हिस्सा लेंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक के पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रार्थना सभा में हिस्सा लेने गांधी आश्रम जाएंगे। वहां पर तमाम नेता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। वर्ष १९३० में यहां साबरमती आश्रम से १२ मार्च को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की थी। वर्ष २०१९ को राष्ट्रपिता की १५० वीं जयंती के तौर पर भी मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा प्रमुख अमित शाह के गृह राज्य में आयोजित की जा रही रैली में कांग्रेस को तीन लाख लोगों के आने की संभावना है। एक महीने के भीतर राहुल गांधी का गुजरात का यह दूसरा दौरा होगा। इससे पहले उन्होंने १४ फरवरी को वलसाड जिले में रैली को संबोधित किया था। वर्ष १९६१ में सीडब्ल्यूसी की बैठक गुजरात के भावनगर में हुई थी।

राहुल, मनमोहन व प्रियंका अडालज में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज वे गांधीनगर अडालज में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करके करेंगे। गुजरात की वर्ष १९६० में स्थापना के बाद १९६१ में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक अहमदाबाद में हुई थी, उसके बाद पहली बार गुजरात में यह बैठक बुलाई गई है। पहले यह बैठक २८ फरवरी को होनी थी, लेकिन भारत व पाकिस्तान की सीमा पर उत्पन्न तनाव के माहौल को देखते हुए बैठक रद कर दी गई थी।

कांग्रेस कार्यसमिति में शामिल कई राष्ट्रीय नेता ११ मार्च को ही अहमदाबाद पहुंच गए थे। राहुल गांधी, डॉ मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी आदि नेता १२ मार्च को सुबह अहमदाबाद के सरदार पटेल एयरपोर्ट से सीधे गांधी आश्रम आएंगे। कांग्रेस ने दांडी मार्च की याद में यहां एक प्रार्थना सभा का आयोजन रखा है। गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी व पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी भी गुजरात से ही लोकसभा चुनाव प्रचार का श्रीगणेश करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावडा के मुताबिक, प्रार्थना सभा के बाद सरदार पटेल स्मारक भवन में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक होगी। इसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति व विविध मुद्दों पर चर्चा होगी। हाल ही में पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए आतंकी हमले व इसके बाद भारत व पाकिस्तान के बीच पैदा हुए जंग के हालात पर भी कांग्रेस नेता चर्चा करेंगे। साथ ही, नोटबंदी, जीएसटी, किसानों की कर्जमाफी, फसल बीमा, राफेल, महंगाई व बेरोजगारी, कांग्रेस छोड़ रहे विधायको के जैसे मुद्दों पर भी इस कार्यसमिति की बैठक में चर्चा होगी। अडालज त्रिमंदिर में एक जनसभा होगी, जिसे सभी बड़े नेता संबांधित करेंगे। प्रियंका गांधी गुजरात में पहली बार किसी जनसभा को संबोधित करेंगी। प्रदेश में पार्टी के पांच लाख सदस्य हैं, इनमें से शक्तिएप के जरिए सक्रिय कार्यकर्ताओं को घर घर संपर्क जैसे कार्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

# वराछा में बस की चपेट में आकर छात्रा घायल

सूरत। शहर के वराछा लाइ ओवरब्रिज पहले पोद्दार आर्केड सर्कल के पास एसटी बस चालक ने साइकिल सवार छात्रा को चपेट में लिया। कक्षा 10 की परीक्षा होने से कृपाली शैलेष पटेल चचेरे भाई के साथ सुबह सात बजे टयुशन जा रही थी। इस दौरान ओलपाड सूरत बगदाणर (जीजे 18 जेड 0242) बस ने साइकिल सवार छात्रा को चपेट में लिया। छात्रा केा निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के बाद बस चालक बस छोड़कर भाग गया। बस यात्री ने कहा कि चालक मोबाइल पर बात कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ। बाद में ट्रैफिक जवानों ने बस को साइड में की। उमिया धाम स्थित रूपा अपार्टमेंट निवासी कृपाली चचेरा भाई डेनिस के साथ जा रही थी। इस दौरान सड़क हादसा हुआ। इसमें बालिका के हाथ में चोट आयी है। सोमवार को वह परीक्षा दे पाएगी या नहीं यह सवाल खड़ा हुआ है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com ( subject to surat jurisdiction)**